

खण्ड A

SECTION A

निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

10×5=50

- (a) “भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) राजनैतिक व्यवस्था द्वारा अनुसरण के लिए अपेक्षित आधारभूत मूल्यों को उपदर्शित करती है।” आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं ? संविधान की उद्देशिका (प्रस्तावना) में लिपिबद्ध मूल्यों का संदर्भ देते हुए व्याख्या कीजिए।

“Preamble of the Indian Constitution is indicative of basic values that the political system is expected to pursue.” How far do you agree with the statement ? Explain with the reference to values that have been enshrined in the Preamble of the Constitution.

10

- (b) “भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद मुख्यतः ‘नाम मात्र के प्रमुख’ के रूप में परिकल्पित है।” इस विषय पर निर्णीत वादों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

“The office of the President under the Indian Constitution has been designed to be largely that of a ‘figurehead’.” Explain, with reference to the cases decided on the subject.

10

- (c) “केन्द्र तथा राज्य के बीच शक्ति वितरण में केन्द्र के प्रति स्पष्ट झुकाव परिलक्षित होता है।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? व्याख्या कीजिए।

“There is an obvious slant in favour of the Centre, in distribution of powers between Centre and States.” Do you agree with the statement ? Explain.

10

- (d) “नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पत्थर में नहीं ढाले गए हैं और समग्र न्याय की माँग की दृष्टि से उनमें स्थापित विधि के सिद्धान्तों से विचलन की सदैव संभावना रहती है।” इस विषय पर विनिश्चित वादों का संदर्भ देकर व्याख्या कीजिए।

“The principles of natural justice are not cast in stone and there is always a possibility of deviation from stated principles of law in view of overall demands of justice.” Explain citing decided cases on the subject.

10

- (e) इस विषय पर निर्णीत वादों का उद्धरण देते हुए प्रशासनिक कार्यवाही के न्यायिक पुनरावलोकन के आधारों की व्याख्या एवं विशदीकरण कीजिए।

Explain and elucidate the grounds of judicial review for administrative action, by quoting decided cases on the subject.

10

(a) "भारत के संविधान में सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों को विशिष्ट प्राथमिकता देते हुए एक तरफ सिविल एवं राजनैतिक अधिकार तथा दूसरी तरफ आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के बीच स्पष्ट अन्तर का प्रावधान किया गया है।" व्याख्या कीजिए।

"The Constitution of India has provided for a clear-cut distinction between civil and political rights on the one hand and economic and cultural rights on the other, with a distinct primacy given to civil and political rights." Explain.

20

(b) "पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक प्रस्थिति प्राप्त है।" भारतीय संविधान में दी गयी पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों के प्राधिकार की परिधि एवं संरचना की व्याख्या कीजिए।

"Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies have been accorded constitutional status." Explain the ambit and structure of the authority of Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies under the Indian Constitution.

15

(c) "भारत का संविधान सिविल सेवकों को संवैधानिक प्रस्थिति तथा संरक्षण प्रदान करता है।" भारत में सिविल सेवकों को क्या-क्या संरक्षण सुनिश्चित किए गए हैं? व्याख्या कीजिए।

"The Constitution of India provides constitutional status and protection to civil servants." What protections have been secured for civil servants in India? Explain.

15

Q3. (a) "चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य निर्वाचन आयोग के पद में निहित है। अतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का निर्णायक महत्त्व है।" अद्यतन न्यायिक विनिश्चयों के संदर्भ में उपर्युक्त कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

"Superintendence, direction and control of elections is vested in the office of the Election Commission and therefore, the appointment of Election Commissioner is of crucial importance in conducting free and fair elections." Critically examine the above statement with reference to recent judicial decisions.

20

(b) "विधिक-सहायता' समाज के गरीब एवं सीमान्त (हाशिए पर) वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच का मूल यंत्र है।" इस विषय में संवैधानिक उपबंधों तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपबंधों की विवेचना एवं विशदीकरण कीजिए।

"Legal-Aid' provides a basic tool for access to justice for poor and marginalized sections of society." Discuss and elucidate the Constitutional provisions and the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987.

15

- (c) “किसी व्यवस्था में ‘एमिनेन्ट डोमेन’ की शक्ति, लोकतांत्रिक संरचना की शक्ति की व्युत्क्रमानुपाती होती है।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? व्याख्या कीजिए।

“The strength of the ‘eminent domain’ is inversely proportional to the strength of democratic structure of any system.” Do you agree with this statement ? Explain.

15

- Q4. (a) किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ठप्प (विराम) हो जाने से आप क्या समझते हैं ? इस बिन्दु पर निर्णीत वादों को उद्धृत करते हुए संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

What do you understand by breakdown of constitutional machinery in a State ? Critically examine the powers of the President in imposing President’s Rule under Article 356 of the Constitution, by citing decided cases on the point.

20

- (b) लोकपाल एवं लोक आयुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल एवं लोक आयुक्त की स्थापना के उद्देश्यों तथा उनकी शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। कथित अधिनियम की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए।

Discuss the objectives of the establishment of Lokpal and Lok Ayukta, and their powers and functions under the Lokpal and Lok Ayuktas Act, 2013. Examine the effectiveness of the said Act.

15

- (c) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि एवं तथ्य का जटिल प्रश्न उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त कर सकता है। उचित उदाहरण देते हुए इस विषय पर उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की भूमिका की विवेचना कीजिए।

If at any time, it appears to the President that a critical question of law and fact has arisen, the President can obtain the opinion of the Supreme Court. Discuss the role of the Supreme Court in this matter, by giving suitable examples.

15



Q6. (a) "विधि को स्थायी होना चाहिए, हालाँकि यह स्थिर नहीं रह सकती है, क्योंकि इसे स्थायित्व एवं परिवर्तन की संविरोधी आवश्यकताओं में सामंजस्य बनाना है और तीव्र विकासमान विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विधि में स्थायित्व अपघटन के रूप में प्रतीत होता है।" उपर्युक्त कथन के आलोक में परम्परागत अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं नवीन अंतर्राष्ट्रीय विधि में भेद बतलाइए।

"Law must be stable, and yet it cannot stand still, as it needs to reconcile the conflicting needs of stability and change and in the fast-developing world, the stability appears to have become the casualty in international law." Differentiate between traditional International Law and new International Law in light of the above statement.

20

(b) "राज्य अपने भूभाग पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को प्रभाव देने के लिए प्रक्रिया में पर्याप्त लचीलापन दर्शाते हैं।" इस विषय पर संगत वादों का उद्धरण देते हुए भारत में अंतर्राष्ट्रीय विधि के मानकों की स्वीकार्यता की व्याख्या कीजिए।

"States show considerable flexibility in the procedures, whereby they give effect to the rules of the International Law, within their territory." Explain the acceptability of norms of International Law in India, citing relevant cases on the subject.

15

(c) 'महाद्वीपीय मग्नतटभूमि (शेल्व)' तथा 'अनन्य आर्थिक परिक्षेत्र' में आप कैसे विभेद करेंगे? सोदाहरण व्याख्या कीजिए।

How do you distinguish between 'Continental Shelf' and 'Exclusive Economic Zone'? Explain giving examples.

15

Q7. (a) "संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना संपूर्ण विश्व में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने में मानवता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है।" संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन लक्ष्यों को किस सीमा तक हासिल किया गया है? व्याख्या एवं विशदीकरण कीजिए।

"Preamble of the UN Charter is representative of the aspirations of humanity in ensuring peace and security across the globe." How far have these objectives been achieved by the UN? Explain and elucidate.

20

(b) "बहुपक्षीय संधि में आपत्ति, संधि के कुछ प्रावधानों की उस राज्य में प्रयोज्यता के विधिक परिणामों को अपवर्जित या उपांतरित करती है।" उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए, जिनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधियों में आपत्तियाँ अनुमन्य हैं।

"Reservation in multilateral treaty excludes or modifies the legal effect of certain provisions of a treaty in its application to that State." Explain the circumstances under which reservations in treaties are permissible under International Law.

15

(e) अंतर्राष्ट्रीय विधि में किन परिस्थितियों में 'बल प्रयोग' या 'आक्रमण' अनुमत्त और न्यायसंगत है ?

Under what circumstances is recourse to 'force' or 'aggression' permissible and justifiable under International Law ?

15

(a) "डब्ल्यू.टी.ओ. (विश्व व्यापार संगठन) अपने सदस्यों के बीच करार के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो कि वैश्विक व्यापार का विधिक आधार सृजित करता है।" नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत डब्ल्यू.टी.ओ. के महत्त्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

"WTO provides a platform for agreements amongst its members which form the legal foundation of global trade." Critically evaluate the importance of WTO in the new international economic order.

20

(b) "संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को मानव पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।" उपर्युक्त कथन के आलोक में मानव पर्यावरण के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों पर प्रकाश डालिए।

"Member States of the UN need to take appropriate action for protecting and improving human environment." In light of the above statement, highlight the major steps of the UN for protecting human environment.

15

(c) "अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को सीमित करने वाले नियमों का समुच्चय है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि अधिकारों के समुच्चय को सुनिश्चित करना चाहती है जो कि मानवों के मानव के रूप में उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं।" अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के बीच उनके अंतर्वस्तु एवं उद्देश्यों के आधार पर विभेद कीजिए।

"International Humanitarian Law is a set of rules to limit the effects of armed conflict, whereas International Human Rights Law seeks to ensure a set of rights which are essential for survival of humans as Humans." Distinguish between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in terms of their contents and purposes.

15

Coll. RY